(घ) पता लगाये गये नये तेल भंडारों से कितना तेल प्राप्त किया जाना हैं और यह कार्य कहां-कहां प्रारंभ हो गया हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) ओ एन जी सी देश में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और उत्पादन में रत हैं । आई ओ सी भी कुछ विदेशी कंपनियों और जो एन जी सी विदेश लिमिटेड के साथ सहयोग करते हुए नए अन्वेषण और उत्पादन व्यावसायिक कार्यो में लगा हैं ।

(ख) तेल और गैस के नए भंडारों का पता लगाने के लिए 1995 -98 के दौरान पश्चिमी और पूर्वी अपतट व असम, अरूणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में भूकंपीय सवेंक्षण और वेधन कार्यकलाप आरंभ कर दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) असम, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और पश्चिमी अपतट में 1995-98 के दौरान 24 स्थनों पर तेल के नए भंडार पाए गए हैं । इन नई खोजों का अनुमानित भंडार (आरंभिक स्थानिक तेल) लगभग 43 एम एम टी हैं । कुछ नई खोजों का अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा हैं ।

कच्चे तेल के भंडारों का सवेंक्षण

1206. **श्री बरजिन्दर सिंह :**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि देश में कच्चे तेल के भंडार की कुल मात्रा की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई व्यापक सवेंक्षण कराया गया हैं,

(ख) यदि हां, तो यह सवेंक्षण कब कराया गया था और उक्त सवेंक्षण के अनुसार देश में पेट्रोलियम का कुल कितना भंडार होने का अनुमान हैं,

(ग) क्या सरकार ने इन भंडारों का भरपूर दोहन करने के लिए कोई समय-समद्ध कार्यक्रम तय किया हैं, और

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, और गत वर्षों में कुल आकलित भंडार का प्रति वर्ष औसतन कितने प्रतिशत उत्पादन किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सवेंक्षण, नए क्षेत्रों की खोज तथा खोजे गए क्षेत्रों से उत्पादन एक सतत एवं जारी रहने वाली प्रक्रिया हैं । कच्चे तेल भंडार प्रत्येक वर्ष सामान्यत : 31 मार्च को नवीनतम निवेशों पर आधारित खोजों तथा अभिवृद्धियों के आधार पर अद्यतन किए जाते हैं । भारत के तेल एवं तेल समकक्ष गैस के भंडार 01 अप्रैल, 1998 को 1459 मिलियन टन अनुमानित किए गए थे । वर्ष 1997-98 के दौरान तेल एवं गैस के स्थानिक अनुमानित भंडारों का 4.1 प्रतिशत उत्पादन किया गया था ।

Funds released to Assam for rural development

1207. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of funds released by Government of Assam for the development of rural areas during the last three years, till date; and

(b) the steps being taken by Government to release more funds to Assam for the development of rural and tribal areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL); (a) Jawahar Rozgar Yojana (JRY), Employment Assurance Scheme (EAS), Million Wells Schemes (MWS), Indira Awaas Yojana (IAY), Integrated Rural Development Programme (IRDP), Development of Women and Children in Rural Areas (DWGRA), Training of Rural Youth for Self Employment (TRYSM), Supply of Improved Toolkits to Rural Artisans (SITRA), National Social Assistance Programme (NSAP), Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) are the major rural development programmes being implemented in Assam. The details of funds released by

Government to Assam during last three years, till date is given in the statement *(sec* below).

(b) It is proposed to earmark 10% of the budget allocation to the North-Eastern States.

Statement -

Release of funds under Rural Development Programmes to Assam during 1995-96, 1996-97, 1997-98 and 1998-99 (Till date)

(Rs. in lakhs)

SI No.	Name of the Scheme	Release of funds by Central Govt, to Assam			
		1995-96	1996-97 ,	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6
1.	JRY	7719.76	3186.83	5524.15	4011.71
2.	EAS	8020.00	10820.00	8592.00	2488.00
3.	MWS	1143.53	1054.14	1210.22	723.35
4.	IAY	2656.32	3157.45	2931.07	3347.27
5.	1RDP	1537.96	1066.76	1425.63	1163.68
6.	DWCRA	158.85	180.89	136.16	118.88
7.	TRYSEM	81.57	105.45	104.33	71.22
8.	TOOLKITS	171.00	114.85	82.85	93.97
9.	NSAP	471.83	697.94	742.41	206.33
10.	ARWSP	2245.00	2353.57	2376.52	2485.48

*Including UNICEF

बंजर भूमि के, विकास हेतु धनराशियों की सी0 ए0 जी0 द्वारा लेखा परीखा

1208. **श्री ओंकार सिंह लखावत :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सी0 ए0 जी0) ने बंजर भूमि के विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए सरकार द्वारा आबंटित धनराशियों के संबंध में लेखा-परीक्षा की हैं, यदि हां, तो ऐसी लेखा-परीक्षा किस-किस वर्ष के लिए की गई हैं और यदि नहीं, तो उसके-क्या कारण हैं,

(ख) क्या सरकार ने बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का पुनरीक्षा, निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करने के लिए कोई कारगर व्यवस्था की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, और

(ग) राजस्थान में बंजर भूमि विकास हेतु आवंटित धनराशियां प्राप्त करने वाले उन संगठनों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में सी0 ए0 जी0 द्वारा लेखा-परीखा की गई और क्या लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आपत्तियां दर्ज की गई हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा आर0 पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां । बंजरभूमि विकास विभाग की स्थापना जुलाई, 1992 में की गई थी । विभाग के कार्यक्रमों की लेखा-परीक्षा प्रधान निदेशक, लेखा-परीक्षा, आर्थिक और सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, के कार्यालय के द्वारा की जाती हैं । अभी तक लेखा-परीक्षा, 31 मार्च 1997 को समाप्त अवधि तक के लिए की गई हैं ।

(ग) राजस्थान में वित्तपोषित किसी भी संगठन के सम्बन्ध में कोई भी लेख-परीक्षा पैरा विभाग में लम्बित नही हैं ।

NGOs blacklisted by Capart

1209. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether nearly 350 Non-Governmental Organisations (NGOs) were blacklisted by Council for Advancement